सत्यमेव जयते

# उत्तराखण्ड

राज्य विधान सभा के वर्ष 2013 के प्रथम सत्र में

# डॉ० अज़ीज़ कुरैशी

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड

का

# अभिभाषण

देहरादून, गुरूवार, 14 मार्च, 2013 (फाल्गुन 23, शक सम्वत्, 1934)

**उत्तराखण्ड राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं विधान सभा के माननीय सदस्यगण;**

मैं आप सभी महानुभावों का वर्ष, 2013 में विधानसभा के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ और देव भूमि उत्तराखण्ड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिये जा रहे सहयोग के लिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता की वर्ष, 2013 में समृद्धि एवं खुशहाली की भी कामना करता हूँ। मुझे आशा है कि नव वर्ष हमें नई शक्ति, नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता प्रदान करेगा ताकि हम प्रदेश और प्रदेशवासियों की सेवा कर सकें।

(1) **मेरी सरकार ने कुशल नीति एवं सतत् प्रयासों से राज्य की वार्षिक योजना** 2012-13 हेतु भारत सरकार से ₹ 8200 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित कराया है जो विगत वर्ष की अपेक्षा अनुमोदित परिव्यय से ₹ 400 करोड़ अधिक है, और

- वार्षिक योजना 2012-13 में ₹ 1500 करोड़ की धनराशि विशेष आयोजनागत सहायता तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के तौर पर परिव्यय अनुमोदित कराया गया है, जो विगत वर्षों की तुलना में क्रमशः ₹ 360 करोड़ व ₹ 600 करोड़ अधिक है। राज्य के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत इन मदों में अभूतपूर्व वृद्धि होना, मेरी सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह धनराशि विगत वर्षों में हिमाचल प्रदेश को दी गयी धनराशि से भी अधिक है।
- केन्द्र द्वारा शत्-प्रतिशत वित्त पोषण वाले निर्माण कार्यों का बिना प्रभार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादन किए जाने का प्रावधान कराया है।
- ग्रीन बोनस की राज्य की प्रबल एवं निरन्तर माँग के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु वित्तीय संसाधनों के आवंटन हेतु नई प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली में पर्यावरण निष्पादन सूचकांक को भी स्थान प्राप्त है।
    - उत्तराखण्ड एट ए ग्लांस 2011–12 का प्रकाशन, तथा प्रदेश में उद्यमिता विकास के व्यापक नियोजन हेतु आर्थिक गणना 2012 और विभिन्न सर्वेक्षणों का कार्य प्रारम्भ किया है।

(2) मेरी सरकार ने **वर्तमान वित्तीय वर्ष में आयोजनागत मदों के अन्तर्गत कुल** बजट का उपयोग करते हुए ढाई सौ कि0मी0 सड़कों का नव निर्माण, साढ़े चार सौ कि0मी0 का पुनःनिर्माण एवं सुधार तथा पैंतालिस सेतुओं का निर्माण कर सड़सठ ग्रामों को जोड़ा है। इसके अतिरिक्त–

- एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुधार कार्यक्रम (यू0एस0आर0आई0पी0) के अन्तर्गत अब तक सड़कों का पुनःनिर्माण एवं सुधार करते हुए पर्याप्त धनराशि का उपयोग किया है।
- अनुसूचित जाति सब प्लान में वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान के अन्तर्गत पन्द्रह गाँवों को मार्गों से जोड़ा है और पर्याप्त सड़कों का पुनःनिर्माण किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन का भी सार्थक उपयोग किया है।
- आम जनता के चहुँमुखी विकास के लिये वर्तमान में निर्मित एक लेन के राज्य मार्गों का दो लेन में परिवर्तन करने, जनपद हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर में रेलवे क्रासिंग पर ऊपरगामी सेतुओं का निर्माण करने, देहरादून शहर में फ्लाई ओवर एवं रिंग रोड का निर्माण करने, विभिन्न श्रेणियों के 1680 असंयोजित ग्रामों को मार्गों से संयोजित किये जाने, प्रदेश में निर्मित कच्चे मार्गों को पक्का किया जाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

(3) **मेरी सरकार उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड** एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (तीन निगमों) के विकास, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण एवं पुनरोद्धार के साथ-साथ उत्तराखण्ड राज्य की जल विद्युत एवं ऊर्जा के अन्य स्रोतों एवं क्षमता के विकास कार्य के लिए दृढ़संकल्पित है और

- व्यासी जल विद्युत परियोजना, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को शीघ्र प्रारम्भ करने का प्रयास कर रही है।
- अब तक लगभग ढाई लाख बी0पी0एल0 (कुटीर ज्योति) संयोजन अवमुक्त कर दिए हैं।

- विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने हेतु एल0टी0 कन्डक्टर को एरियल बन्च कन्डक्टर (ए0बी0सी0) से बदलने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि विद्युत चोरी पर अंकुश लग सकेगा।
- देहरादून में एक अत्याधुनिक स्वतंत्र प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र की स्थापना की गयी है। इसमें प्रत्येक समय पर ग्रिड की निगरानी एवं लोड डिस्पैच का कार्य सुगम तरीके से सम्पन्न कराने में आधुनिक तकनीक के उपकरण एवं सॉफ्टवेयर लगाये गये हैं। इससे स्वतन्त्र एवं प्रभावी ग्रिड की प्राप्ति होगी। ऋषिकेश एवं काशीपुर में एक-एक सब लोड डिस्पैच सैन्टर का निर्माण प्रस्तावित है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम, सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र स्थापना, फैमिली साईन बायोगैस संयंत्र, घराट सुधारीकरण, बायोगैस से विद्युत उत्पादन ऐरौजनरेटर की स्थापना पर विशेष बल दे रही है तथा ऊर्जा संरक्षण विन्डिंग कोड नीति को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

**(4) मेरी सरकार गौरा देवी वाटर पार्क योजना के तहत तालाब, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों** के खेलने हेतु पार्क;

- फूड कॉर्नर, शौचालय एवं वाहनों के लिए पार्किंग आदि का निर्माण कार्य;
- डिस्पैंसरी रोड देहरादून के पास तीन सौ वाहनों की पार्किंग हेतु बहुमंजिला पार्किंग स्थल का निर्माण कार्य;
- देहरादून में लगभग डेढ़ एकड़ भूमि पर पशु चिकित्सालय एवं कर्मचारियों हेतु स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य;
- राजपुर रोड सौन्दर्यीकरण का कार्य व देहरादून में ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्टेशन की समस्याओं को दूर करने हेतु बुद्धा चौक, लैन्सडाउन चौक का कार्य;
- मसूरी में आर्थिक रूप से कमजोर एवं दुर्बल आय वर्ग हेतु कुल दो सौ आवासीय भवनों के निर्माण संबंधी योजना का कार्य;

- देहरादून रेलवे स्टेशन को पी0पी0पी0 मोड पर देहरादून से हर्रावाला स्थानान्तरित करने हेतु हर्रावाला अवस्थापना कार्य एवं एक्सप्रैस हाईवे का निर्माण कार्य;
- आई0एस0बी0टी0 देहरादून के निकट एक्वैरियम कम होटल कम कन्वैंशनल सेन्टर, मसूरी ईको पार्क विकास परियोजना में ईको फ्रैंडली कॉटेज का निर्माण कार्य;
- हरिद्वार में इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत लगभग पचास दुर्बल आय वर्ग (वन रूम फ्लैट) के भवनों का निर्माण कार्य;
- ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत सड़कें, नाला, नाली, जलापूर्ति व्यवस्था, सीवर व्यवस्था एवं विद्युत व्यवस्था का कार्य;
- हरिद्वार, ऋषिकेश तथा मुनिकीरेती में पूर्व से निर्मित लगभग पिछहत्तर पार्कों में उद्यानीकरण, सौन्दर्यीकरण आदि का कार्य पार्क के अन्तर्गत व्यक्तियों को बैठने हेतु प्री-कास्ट कंक्रीट चेयर टाईप बैंच, तथा बच्चों को खेलने के लिये फिसलन पट्टी का कार्य तेजी से सम्पादित कर रही है तथा;
- नजूल भूमि पर अध्यासित एवं काबिज व्यक्तियों को वर्ष 2000 के सर्किल रेट की दरों पर फ्री होल्ड की सुविधा प्रदान करते हुए नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु नजूल नीति की अवधि को बढ़ा चुकी है।

(5) **मेरी सरकार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (केन्द्र सहायतित), कम लागत** के व्यक्तिगत शौचालय (केन्द्र सहायतित), जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत संचालित उपघटक योजनाएं (केन्द्र सहायतित) के अधीन, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड गर्वनेन्स, बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डवलपमेन्ट प्रोग्राम, यूआईडीएसएसएमटी वाह्य सहायतित योजना अवस्थापना विकास योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि, हाईटैक शौचालयों का निर्माण, आश्रयहीन लोगों के लिये रैन बसेरा का निर्माण, राजीव गाँधी आवास योजना का क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक कर रही है।

(6) मेरी सरकार उच्च शिक्षा के ठोस सुदृढ़ीकरण हेतु कृत संकल्प है। देहरादून को शिक्षा हब के रूप में तैयार करने के प्रयोजन से मेरी सरकार ने चार नये निजी विश्वविद्यालयों का गठन किया है। इनसे राज्य के छात्रों को विभिन्न संकायों में पाठ्यक्रम को ग्रहण करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय तथा उसकी शाखाओं में छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए हर सम्भव सुविधाएँ अनुमन्य कराने हेतु कटिबद्ध है।

मेरी सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अद्यतन सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लगभग नौ हजार तीन सौ बच्चों को असहायतित विद्यालयों में प्रवेश देकर अधिनियम का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लगभग सात लाख अस्सी हजार बच्चों को यूनीफॉर्म, प्रथम बार विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र के आरम्भ में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, प्रथम बार प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संकुल से राज्य स्तर तक खेलकूद प्रतियोगिताओं को सम्पन्न कराने के लिए अलग से कार्ययोजना तैयार कर प्रतियोगिताएं सम्पन्न कराई गयी हैं तथा तेरह राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों में से पाँच विद्यालयों को पी0पी0पी0 मोड व शेष आठ को सोसाइटी मोड में संचालित किये जाने की कार्यवाही की है।

प्रदेश के युवाओं को रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के लिए उधमसिंहनगर के खटीमा, बाजपुर, चमोली के गैरसैण, अल्मोडा के दन्या, जनपद–टिहरी के गजा एवं प्रतापनगर, नैनीताल के रामनगर, जनपद–देहरादून के क्वांसी(चकराता), चम्पावत् के टनकपुर एवं टिहरी के जाखणीधार नामक स्थान पर डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए राजकीय पॉलीटैक्निक संस्थानों की स्थापना किये जाने का निर्णय मेरी सरकार द्वारा लिया गया है।

- मेरी सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से पी0पी0पी0 मोड के अंतर्गत वर्तमान में बयालिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया जा चुका है। इससे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा।

- मेरी सरकार ने सीमांत जनपद–चमोली के जिला मुख्यालय-गोपेश्वर की परिधि के अन्तर्गत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज की स्थापना गत वर्ष भारत सरकार के सहयोग से की है।

**(7) जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण** है। आम जनों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। पेयजल सुधार हेतु मेरी सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ-साथ स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के चयनित तीन नगरों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में पेयजल सुविधाओं में सुधार के कार्य सरकार सफलतापूर्वक पूर्ण कर रही है। पतित पावनी गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए गंगा कार्य योजना, प्रथम चरण में निर्मित परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु पोषित गंगा कार्य योजना कार्यक्रम को मेरी सरकार संचालित कर रही है। सरकार ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट को दूर करने के लिए कटिबद्ध है।

**(8) मेरी सरकार भवन विहीन चिकित्सालयों हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के** निर्माण हेतु एवं निर्माणाधीन भवनों हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करने, एस0सी0एस0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत भवनों के निर्माण/निर्माणाधीन कार्यों हेतु पर्याप्त धनराशि अवमुक्त करने, जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत हेतु पर्याप्त धनराशि अवमुक्त करने, और

- राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में सी0सी0आई0एम0 मानकों के अनुसार भवनों के निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु पर्याप्त बजट स्वीकृत करने की कार्यवाही की है।

- मेरी सरकार द्वारा चिकित्सा विहीन क्षेत्रों में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु बीस चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है;

- प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयुष ग्राम की स्थापना एवं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त बजट प्रस्तावित किया है, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में पाँच अन्य नये विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य रखा है;
- केन्द्रीय योजनान्तर्गत पचास राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के उच्चीकरण किये जाने हेतु योजना प्रस्तावित की है;
- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के प्रशिक्षण की योजना एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत प्रस्तावित है;
- जनपद देहरादून के विश्वविद्यालय परिसर में केन्द्रीय योजनान्तर्गत पचास शैय्यायुक्त चिकित्सालय की स्थापना हेतु निर्माण कार्य कराना प्रस्तावित किया गया है।
- मेरी सरकार विभिन्न जनपदों में जनजाति उपक्षेत्र योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत तीन राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना एवं अनुसूचित जाति योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत तीन राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है;
- राज्य में गुणवत्तापरक चिकित्सा तथा निदान सुविधायें उपलब्ध कराने में मानव संसाधन की कमी एक महत्वपूर्ण कारक के रुप में सामने आई है। इस कमी को दृष्टिगत रखते हुये दुर्गम, असेवित व दूरस्थ क्षेत्रों में सार्वजनिक व निजी सहभागिता के अन्तर्गत मोबाइल चिकित्सालयों का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- सरकार संकट की घड़ी में जनसामान्य को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराते हुये निकटतम चिकित्सा इकाई तक निःशुल्क पहुँचाने के लिये 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा तथा बोट एम्बुलेन्स सर्विस राज्य के असेवित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से सभी जिलों में अति आधुनिक उपकरणों युक्त सचल चिकित्सा वाहनों का संचालन कर रही है।

- पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून में मै0 फोर्टिस हैल्थ केयर प्रा0 लि0 की सहभागिता से कार्डियोलोजी सेन्टर एवं मैसर्स अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई तथा बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में मै0 राही केयर प्रा0 लि0 की सहभागिता से नैफ्रोलॉजी यूनिट का संचालन किया जा रहा है।
- राज्य कर्मचारियों को नगद रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यू-हैल्थ स्मार्ट कार्ड योजना प्रारम्भ की गयी है। राज्य के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गयी है। इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय एवं संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार में डाइग्नोस्टिक सेन्टर स्थापित करने, मानव संसाधनों की अत्यन्त कमी के कारण सोलह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लोक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित करने, प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु टॉल फ्री नं0 104 पर चिकित्सकों से परामर्श पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, दिये जाने हेतु सरकार कटिबद्ध है।

(9) **मेरी सरकार ने लघु सिंचाई के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत गूल निर्माण,** सिंचाई हौज, हाईड्रम, बोरिंग पम्पसैट, गहरे/मध्यम नलकूप, आर्टीजन वैल, छोटे गेटेड वियर एवं भूस्तरीय पम्प सैटों का निर्माण/ स्थापना करके पर्याप्त सिंचन क्षमता का सृजन किया है।

- सरकार जिला योजना, नाबार्ड वित्त पोषण, केन्द्र पुरोनिधानित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, केन्द्र पोषित बाढ़ सुरक्षा मद तथा राज्य सैक्टर मदों के कार्य को शीघ्रता से सम्पादित कर रही है।
- सरकार जल संवर्द्धन के अन्तर्गत जलाशयों के निर्माण, पर्यटन की दृष्टिकोण से सिंचाई विभाग के विश्राम गृहों को सुसज्जित करना, पानी की कम उपलब्धता की स्थिति में सिंचाई हेतु अधिकतम उपयोग हेतु ड्रिप/माइक्रो स्प्रिंकलर योजनाओं के निर्माण पर बल दिये जाने को प्राथमिकता दिये जाने, सिंचाई योजनाओं को बहुउद्देशीय बनाने पर बल दिये जाने, सिंचाई हेतु निर्मित जलाशयों में नौका विहार, मत्स्य पालन एवं सिंचाई विभाग की भूमि से पार्किंग शुल्क आदि लेकर राजस्व में वृद्धि करने, अल्मोड़ा शहर एवं इसके

समीपवर्ती ग्रामों को पेयजल आपूर्ति हेतु कोसी नदी में कोसी कस्बे के समीप बैराज के निर्माण हेतु विशेष योजनागत सहायता के अन्तर्गत निर्माण किये जाने, बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत बैजनाथ झील का निर्माण करने, जमरानी बाँध परियोजना का निर्माण गोला नदी पर करने, सौंग बाँध परियोजना देहरादून के पास सौंग नदी पर बनाये जाने के लिए संकल्पबद्ध है।

सरकार जलागम विकास परियोजनाओं के सफल संचालन कराने के लिए वचनबद्ध है।

सरकार वित्त, औद्योगिक विकास, कृषि, समाज कल्याण, ऊर्जा, वन, चीनी एवं गन्ना विकास, खाद्य विभाग की समितियों के हस्तान्तरण हेतु निरन्तर प्रयासरत है। कतिपय विभागों की परिसम्पत्ति का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे मामलों के निस्तारण में सरकार त्वरित गति से कार्यवाही कर रही है।

**(10) मेरी सरकार महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण में** सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला पौधशालाओं की स्थापना कर रही है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके; और

- वानिकी कार्यों में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ईको-टॉस्क फोर्स के माध्यम से प्रदेश के दुर्गम स्थलों जैसे माणा, महरगाँव, मलारी (चमोली), सिरकुच एवं मूनाकोट (पिथौरागढ़) में वनीकरण कार्य कर रही है।
- राज्य में प्रथम बार वन क्षेत्र में सत्रह विरासती स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है। पारिस्थितिकीय पर्यटन के अन्तर्गत जैव विविधता संरक्षण तथा पर्यटन के माध्यम से राजस्व में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य में पारिस्थितिकीय पर्यटन को राजस्व अर्जन के साथ-साथ स्थानीय निवासियों की आय में वृद्धि के स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से मसूरी में धनोल्टी में धरा और अम्बर नाम से दो ईको-पार्कों को विकसित किया जाना है। इन

पार्कों का संचालन ग्राम वासियों द्वारा गठित ईको-विकास समिति के माध्यम से किया जाएगा।

**(11) मेरी सरकार ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सुनियोजित एवं त्वरित** समेकित विकास हेतु विभिन्न विधाओं तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि, पर्यटन संसाधन विकास, प्रचार-प्रसार एवं पर्यटन विपणन, पर्यटन आधारित शिल्प उद्योग को प्रोत्साहन आदि पर्यटनोपयोगी गतिविधियों को चुनौतीपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है जिससे उत्तराखण्ड को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सके।

- मेरी सरकार द्वारा पर्यटकों/यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये, जो यात्री पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "जानकीचट्टी-यमुनोत्री तथा ठुलीगाड़-पूर्णागिरी रोपवे परियोजनायें" पी0पी0पी0 मोड पर क्रियान्वित करने तथा कद्दूखाल, सुरकण्डा देवी रोप वे परियोजना भी व्यय निवेशकों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
- विभिन्न अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों यात्रा मार्गों पर विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के विकास विभिन्न सर्किटों, डेस्टिनेशनों, मेगा सर्किट, होटल प्रबन्धन संस्थान, पर्यटन ग्रामों को लार्ज रेवन्यू गिरीरेटिंग योजना के अन्तर्गत मसूरी से हाथीपॉव तक रज्जुमार्ग की परियोजना तथा मेले एवं त्यौहारों के आयोजन हेतु विभिन्न परियोजनायें विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा है।
- 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत चीला एवं कौडियाला में ईको टूरिज्म के रूप में विकास, गढ़वाल मण्डल एव कुमाँऊ मण्डल के विभिन्न स्थलों पर सुलभ शौचालयों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, नव निर्माण के कार्य करवाये जाने का लक्ष्य रखा है।

- ए0डी0बी0 (एशियन डेवलपमेंट बैंक) द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु रुपये तीन सौ करोड़ की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर ली गयी है, जिसके अन्तर्गत आसन बैराज, यमुना सर्किट के अन्तर्गत टाईगर फॉल, देवबन, हनोल, महासू मन्दिर एवं लाखामण्डल, वाटर स्पोर्ट्स के अन्तर्गत हरिद्वार में पुरानी गंग नहर में जलक्रीड़ाओं में सुविधायें, जगजीतपुरा नहर का सौन्दर्यीकरण, नौकुचियाताल में पर्यटक आवास गृह का निर्माण एवं अन्य पर्यटक सुविधायें, पिथौरागढ़ फोर्ट का संरक्षण, मोस्टमानु मन्दिर पिथौरागढ़ का पिकनिक स्पॉट, चण्डाक ट्रैक एवं व्यू प्वाईन्ट्स का विकास, कोटद्वार से प्रवेश सुविधाओं का विकास, डाकपत्थर, पिरान कलियर रूद्रपुर, भीमताल, पिथौरागढ़, कोटद्वार, टिहरी, अल्मोड़ा, रायपुर में एडवेन्चर टूरिष्ट सेन्टर्स का विकास एवं निर्माण की परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है।
- पर्यटन ग्राम योजना के अन्तर्गत मोटाड़, अगोड़ा(उत्तरकाशी), कोटी, इन्द्रौली एवं पत्यूड़ (देहरादून) एवं सारी-देवरियाताल (रूदप्रयाग) में हार्डवेयर प्रोजेक्टों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है।
- साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न विधाओं यथा रीवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, माउन्टेनियरिंग, रॉक क्लाइमिंग आदि का प्रशिक्षण प्रदान दिया गया है।
- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में लगभग डेढ़ सौ व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।
- श्री नन्दा राजजात-2013 के सफल आयोजन हेतु "नौटी-कंश्वा-चांदपुरगढ़ी-सेम हेरीटेज एवं ईको टूरिज्म सर्किट" एवं "कुरूड़-नन्द केशरी-वाण, वन-बेदनी झील हैरीटेज एवं ईको टूरिज्म सर्किट" तथा उत्तराखण्ड में जन सुविधाओं के विकास हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(12) **मेरी सरकार वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों, साहित्यकारों को मासिक पेंशन** का भुगतान कर रही है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति योजनान्तर्गत कलाकारों,

सांस्कृतिक दलों को चरणबद्ध रूप से पारम्परिक वाद्ययंत्रों एवं वेश-भूषा भी क्रय कर, उपलब्ध करा रही है, मूर्धन्य साहित्यकारों, लेखकों, कवियों जिनकी कृतियां धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती हैं, ऐसे साहित्यकारों, लेखकों, कवियों को उनकी कृतियों के प्रकाशनार्थ वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है, प्रदेश के स्थाई मूल निवासी, जिन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण की है, को सरकार रुपये पच्चीस हजार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। महान विभूतियों व शहीदों की स्मृति में मूर्तियों, शहीद स्मारकों का निर्माण कर रही है। प्रदेश की प्राचीन धरोहरों के संरक्षण, संवर्द्धन हेतु कार्य कर रही है। यत्र-तत्र बिखरी पुरासम्पदा धरोहरों को संरक्षित की दिशा में कार्य प्रगति पर है।

(13) मेरी सरकार ने राज्य में नियमित हवाई सेवाओं को बनाए रखने, तीर्थाटन के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा अनुमन्य कराने, नये हेलीड्रम की स्थापना करने तथा हवाई पट्टियों के विस्तारीकरण एवं सुधारीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

(14) मेरी सरकार ने राज्य में रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिए इसे मनोरंजन कर से मुक्त करने का निर्णय लिया है।

(15) मेरी सरकार पट्टेदारों को संक्रमणीय अधिकार देने की कार्यवाही शीघ्रता से कर रही है। इसके अधीन अब तक लगभग पैंसठ किसान लाभान्वित हो चुके हैं; और

- गैर वन भूमि को बी0पी0एल0 श्रेणी, निर्बल वर्ग भूमिहीन परिवारों तथा प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए परिवारों को आवास स्थल तथा गौशाला प्रयोजन के लिए एक सौ अस्सी गज भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।
- राज्य की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में सार्थक कार्यवाही की है।
- चकबन्दी के क्षेत्र में भी शीघ्र कार्यवाही करने की पक्षधर है।
- राजस्व से सम्बन्धित वादों के निस्तारण के लिए विभिन्न पहलुओं पर कार्य करते हुए आवश्यक न्यायालयों के गठन कर ठोस कार्यवाही कर रही है।
- सेवाओं यथा आय, जाति, निवास, हैसियत, चरित्र, इत्तरजीवी/पारिवारिक सदस्यता, स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित, दैवीय आपदा, मुख्यमंत्री राहतकोष,

खतौनी, खसरे की कम्प्यूटरीकृत प्रति एवं किसान बही आदि को समयबद्ध रीति से निस्तारण करने की कार्यवाही की है।

- आम जन की कठिनाइयों के निराकरण, स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन की स्थापना तथा आम जन द्वारा की गयी शिकायतों, परिवादों का समयबद्ध रूप से निस्तारण सुनिश्चित किये जाने व ''शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ'', हेतु प्रत्येक जिले व मण्डल में क्रमशः मण्डलायुक्त कार्यालयों में ''शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ'' गठित किया है।

**(16) मेरी सरकार 13वें वित्त आयोग की संस्तुति पर राज्य के सभी जिलों में न्याय** सदन स्थापित करने हेतु कटिबद्ध है और इस दिशा में कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया है।

**(17) मेरी सरकार ने निर्धारित कार्यक्रमानुसार 01 जनवरी, 2013 की अर्हता तिथि के** आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन कर लिया है।

सरकार द्वारा केन्द्र की न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन कार्य को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण अकुशल श्रमिकों हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना तथा ग्रामीण आवास हेतु इन्दिरा आवास योजना एवं ग्रामीण संयोजकता हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सक्रियता पूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है; और

- लगातार हो रहे पलायन को कम करने में उत्तराखण्ड हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना अपने विभिन्न घटकों जैसे कृषि, औद्यानिकी, मृदा एवं जल संसाधन, पशुपालन, वानिकी, ईको-पर्यटन एवं गैर कृषि गतिविधियों के माध्यम से सहयोग दिया है।
- उद्यानिकी उपघटक, मृदा एवं जल संसाधन, डेयरी उपघटक, दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री शिल्प विकास योजना महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, ग्रामीण आवास योजना,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

(18) **मेरी सरकार के द्वारा औद्यानिक उपजों के विपणन, भण्डारण एवं प्रसंस्करण हेतु** नीतिगत निर्णय लिए जाने के लिए औद्यानिक उपजों के आंकड़ों का सर्वे कराया जा रहा है; और

- नेशनल मिशन ऑन माइक्रोइरिगेशन, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन पर कार्य कर रही है।
- मसाला पार्क की स्थापना उद्यान कार्ड वितरण, रोपण सामग्री, घेरवाड़ योजना फसल बीमा योजना, पुष्प विकास, सिल्क पार्क की स्थापना, चाय विकास औषधीय एवं सगन्ध पादपों का विकास तथा जड़ी बूटी मिशन की और विशेष ध्यान दे रही है, जिससे राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके।

(19) **उत्तराखण्ड राज्य के सत्तर प्रतिशत ग्रामीणों की आजीविका का** मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। राज्य में कुल सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का लगभग पाँच प्रतिशत योगदान है जो कि पशुपालन व्यवसाय की महत्ता दर्शाता है। पशुपालन विभाग पशुधन नीति बनाने और लागू करने, पशु रोगों के नियंत्रण के लिये आनुवंशिक संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन एवं उन्नयन, पोषक आहार एवं चारे की उपलब्धता बढ़ाने, विपणन सुविधाओं के चिरस्थायी विकास और पशुधन उद्यमों के उत्पादन में पशुपालन विभाग अग्रसर है।

पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं खेती योग्य भूमि की कमी के कारण वर्ष भर पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने, महिलाओं के बोझ को कम करने के उद्देश्य से राज्य में वन पंचायतों में चारे का उत्पादन करने, पशुपालकों के पशुओं के सम्बर्द्धन एवं विकास हेतु विभिन्न कायक्रमों (चिकित्सा, टीकाकरण, बधियाकरण, सामूहिक दवापान, कृत्रिम गर्भाधान बांझपन निवारण) के माध्यम से सम्पादित करने, हेतु संकल्पबद्ध है।

(20) **मेरी सरकार बाजपुर तथा किच्छा चीनी मिलों में विद्युत उत्पादन हेतु विद्युत** सह-उत्पादन इकाईयाँ (Co-Generation Units) की स्थापना किये जाने के साथ ही बाजपुर आसवानी का आधुनिकीकरण भी करने पर विचार कर रही है। इसके अन्तर्गत द्वितीय चरण में डोईवाला, नादेही, गदरपुर एवं सितारगंज में भी विद्युत सह-उत्पादन किये जाने हेतु प्रयासरत् है। इसके अतिरिक्त सरकार ने अगहन, गन्ने का मूल्य रुपये दौ सौ पिचानवे तथा सामान्य गन्ने के लिए रुपये दौ सौ पिचासी कुन्तल का समर्थन मूल्य घोषित किया है, जो अन्य राज्यों से अधिक है।

(21) **सहकारिता का दृष्टिकोण राज्य के विभिन्न अंचलों के निर्बल वर्गों को** समृद्धशाली बनाते हुए उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है।

- पैक्स को बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों के रूप में विकसित करने, सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन कार्य समयान्तर्गत, सम्पन्न कराने तथा सहकारिता विभाग के सम्पूर्ण संस्थागत ढांचे को ई-गवर्नेंस के अन्तर्गत लाये जाने हेतु संकल्पबद्ध है।

(22) **सरकार राज्य की जनता के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उनकी बेहतरी के** लिए संसाधन बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस दिशा में कार्य करते हुए सघन तलाशी में कर अपवंचन से राजस्व में अतिशय वृद्धि हुई है।

- सरकार ने अपने परिवहन बस बेड़े में आवश्यकतानुसार विस्तारीकरण किया है।

(23) **सरकार अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य** में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक योजनाऐं चलाई जा रही हैं। ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय के लिये अलग विभाग गठित किया है;

- सरकार अल्पसंख्यकों हेतु मुख्य कल्याणकारी कार्यक्रम बनाने हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना, जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों

का अधिष्ठान की स्थापना एवं अल्पसंख्यक कल्याण भवन निर्माण करने के लिए संकल्पबद्ध है।

- मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक कल्याण एवं निःशक्त जनों को उनकी क्षमता के अनुसार योग्य बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु प्रयत्नशील है।
- अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास कार्यक्रम में प्राइमरी से उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा तक छात्रवृत्ति तथा पाठ्य पुस्तकों के साथ ही उपकरणों के लिए सहायता प्रदान कर रही है, प्रत्येक जिलों में निःशुल्क छात्रावासों की व्यवस्था की गई है।
- अनुसूचित जाति के छात्रों के स्तर को ऊपर उठाने हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की गयी है तथा अनुसूचित जाति के छात्रों की तकनीकी शिक्षा हेतु तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं सामान्य बालिकाओं हेतु कन्या धन योजना के अन्तर्गत रूपये पच्चीस हजार राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के प्रतिभावान छात्रों हेतु कालसी देहरादून में एकलव्य विद्यालय की स्थापना के साथ ही आई०ए०एस०, पी०सी०एस० की प्री कोचिंग निजी संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के छात्रों हेतु लैपटॉप दिये जाने प्रस्तावित हैं तथा महिलाओं एवं पुरुषों को साड़ी व कम्बल वितरण किया जाना प्रस्तावित है।
- रुड़की में वृद्ध, अशक्त व्यक्तियों हेतु गृह निर्माण की योजना है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों अथवा रूपये बत्तीस हजार तक वार्षिक आय वाले आवासहीन परिवारों को आवास एवं शौचालय उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

- आदिम जनजातियों, बुक्सा एवं राजी जातियों के विकास हेतु शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।
- जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के सात सौ तेरह एवं अनुसूचित जन जाति के छः सौ पिचानवे परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

**(24) सरकार अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ सभी अर्ह परिवार को दिये जाने** हेतु कृत संकल्प है। राज्य के सभी अर्ह परिवारों को चीनी, मिट्टी तेल, एल0पी0जी0 का लाभ अनुमन्य कराया गया है। मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ एवं चावल यथा आवंटन आवश्यकतानुसार क्रय किया गया है।

**(25) सरकार उत्तराखण्ड में मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित करने हेतु औद्योगिक** विवादों के निस्तारण में द्विपक्षीय वार्ता की संस्कृति विकसित करना, उत्पादन क्षेत्र के साथ जनहित सेवा प्रदाय संस्थाओं में कार्य संस्कृति और कौशल विकसित करना, न्यूनतम श्रम मानकों को प्रभावी ढ़ंग से लागू करना, बाल, बंधुआ श्रम की सामाजिक बुराई की रोकथाम की दिशा में तत्संबंधी कानूनों को प्रभावी ढ़ंग से लागू करना, महिला श्रमिकों को शोषण से बचाना, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, संबंधित स्रोतों से सुझाव आमंत्रित कर श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा के कानूनों को युक्त संगत और सरल बनाना तथा निरीक्षण व्यवस्था को सुगम एवं पारदर्शी बनाना, प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ संगठित, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को श्रम कानूनों के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एवं श्रमिकों के कल्याणार्थ योजनाएं तैयार कर उन्हें कार्यांवित करने हेतु सरकार कटिबद्ध है।

- राज्य, केन्द्रीय अधिनियमितियों के अधीन मेरी सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कटिबद्ध है।
- सरकार ने सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार सह कौशल विकास भत्ता योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना हेतु अब तक लगभग डेढ़ हजार लाभार्थियों को चयनित किया है।

- सरकार ने सेवायोजन कार्यालय, रूद्रप्रयाग, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, टिहरी में समूह ''ग'' बैंक प्रोबेशनरी अधिकारी, लिपिक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु समय–समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया है।

(26) **मेरी सरकार विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य के** प्रति गम्भीर है। इस क्रम में राज्य में वर्तमान में कुल पन्द्रह औषधालय स्थापित हैं। सरकार ऐसे श्रमिकों को राज्य, केन्द्रीय अधिनियमों में दी गयी सुविधाओं को अनुमन्य कराने के लिए कटिबद्ध है।

- सरकार खटीमा, किच्छा एवं सितारगंज (उधमसिह नगर) एवं हल्द्वानी क्षेत्र में नये औषधालय स्थापित किये जाने;
- जनपद देहरादून के तरला नागल क्षेत्र में डाईग्नोस्टिक सेन्टर स्थापित किये जाने;
- देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में औषधालय एवं स्थानीय कार्यालय हेतु भूमि प्राप्त कर, सुद्धोवाला में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सालय, निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय व आवासीय परिसर स्थापित किये जाने हेतु भूमि प्राप्त करने;
- सिडकुल क्षेत्र हरिद्वार में चिकित्सालय निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने;
- हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जाने हेतु भूमि प्राप्त करने;
- उधमसिंह नगर के रूद्रपुर एवं काशीपुर क्षेत्र में एक-एक कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय की स्थापना हेतू भूमि प्राप्त करने;
- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों-लढ़ौरा, हरिद्वार, डोईवाला क्षेत्र, देहरादून, लक्सर हरिद्वार, मंगलौर-झबरेड़ा हरिद्वार, लालतप्पड़ देहरादून, सिडकुल व्याप्त क्षेत्र हरिद्वार एवं आई0टी0 पार्क देहरादून में औषधालय स्थापित किये जाने संबंधी कार्यवाही करने; तथा

- पाँच नये स्थानों (श्रीनगर, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा) में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तारीकरण किये जाने संबंधी कार्यवाही को त्वरित गति से सम्पादित करने के लिए कटिबद्ध है।

(27) **मेरी सरकार प्रदेश के नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु समाज के** प्रत्येक वर्ग के सहयोग एवं सहभागिता से विधि सम्मत् सुरक्षा, शान्ति एवं कानून-व्यवस्था को बनाये रखने, निरन्तर परिवर्तनशील सामाजिक परिवेश में पुलिस व्यवस्था के समक्ष उभरती हुई चुनौतियों यथा समाज में पनपती समसामयिक एवं संगठित अपराधों के अनावरण एवं उन पर प्रभावी नियंत्रण, प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों, सुरम्य पर्यावरण एवं नागरिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण तथा जनता के प्रति जवाबदेह एवं कानून के प्रति समर्पित प्रदेश के पुलिस बल के उक्त दायित्वों एवं कार्यों के निर्वहन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

- समाज में विधि के प्रति सम्मान एवं विधिपूर्ण कार्य प्रणाली स्थापित कर अपराधों पर नियंत्रण एवं निवारण हेतु प्रभावी पैरवी कर समाज में सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, एकता एवं अखण्डता को अक्षुण बनाये रखने में सरकार सफल रही है।

- अपराधों पर नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु समय-समय पर ठोस कदम उठाये गये हैं। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा हेतु निरन्तर चौकसी की प्रभावी कार्यवाही प्रचलित है। प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों, सैनिक एवं राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक प्रमुख तीर्थ स्थलों एवं पर्यटन स्थलों की सुरक्षा एवं उनकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत् प्रदेश में शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु समुचित प्रशिक्षित पुलिस बल गठित किया गया है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों, प्रतिष्ठानों एवं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ की गयी है। आतंकवादी एवं उग्रवादी गतिविधियों से निपटने हेतु राज्य में आतंकवाद निरोधी दस्ते तथा अराजक तत्वों द्वारा आयोजित संगठित अपराधों पर नियंत्रण हेतु प्रदेश के

प्रत्येक जनपद में त्वरित प्रतिक्रिया टीम गठित की गयी है, जिससे इस प्रकार की घटनाओं एवं अपराधों पर अंकुश एवं तत्काल नियंत्रण किया जाता है।

- राज्य के पुलिस बल की क्षमता, अनुशासन एवं आधुनिकीकरण में अभिवृद्धि के दृष्टिगत् पुलिस विभाग में रोजगार के अवसर सृजित किये गये हैं, जिसका प्रत्यक्ष लाभ प्रदेश की जनता को प्राप्त हुआ है। प्रदेश के पुलिस बल को यथोचित उपयोगी प्रशिक्षण, वाहन, शस्त्र एवं संयत्रों से सुसज्जित किये जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरुप पुलिस बल का राष्ट्रीय परिदृश्य एवं अन्य प्रदेशों की तुलना में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण है।

- सरकार ने पुलिस बल के अनुपूरक संगठन के रुप में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा जनसामान्य की सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबन्धन में बचाव राहत एवं सहयोग तथा प्रदेश के प्रमुख नगरों के यातायात नियंत्रण में होमगार्ड्स् स्वयं सेवकों द्वारा अपना सहयोग ले रही है। जनपद देहरादून के कोटला सन्तूर, विकासनगर में केन्द्रीय होमगार्ड्स् एवं नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार का भी सहयोग प्राप्त किया गया है। इस प्रशिक्षण संस्थान में यथाशीघ्र प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

- सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमूल्य योगदान के दृष्टिगत् उनको यथोचित् सम्मान एवं सुविधायें प्रदान की गयी हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानजनक मासिक, पारिवारिक पेंशन प्रदान की जा रही है तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा, परिवहन, शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थानों में प्रवेश तथा सेवायोजन में आरक्षण, राजकीय अतिथि गृहों में शासकीय दरों पर अधिवास की सुविधा अनुमन्य की जा रही है। राष्ट्रीय पर्वों एवं राज्य में सार्वजनिक समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है।

- प्रदेश के राज्य निर्माण आन्दोलनकारियों का सम्मान करते हुए सरकार द्वारा उन्हें यथोचित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसके अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर नियुक्ति में आरक्षण, आन्दोलनकारियों के स्वयं के सेवायोजन हेतु इच्छुक न होने पर उसके परिवार के एक आश्रित को सीधी भर्ती में दस प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण की सुविधा, एक सप्ताह से कम अवधि के लिए जेल गये आन्दोलनकारियों को स्वरोजगार की योजनाओं में प्राथमिकता तथा ऐसे आन्दोलनकारियों, जिन्हें किन्हीं कारणवश सेवायोजित नहीं किया जा रहा है, को आजीवन प्रतिमाह ₹ 3000 जिसे निकट भविष्य में बढ़ाया जाना प्रस्तावित है व निःशक्त आंदोलनकारियों को ₹ 10000 प्रतिमाह पेंशन की सुविधा प्रदान की जा रही है।

(28) सरकार नन्दा देवी कन्या धन योजना, सबला योजना, किशोरी शक्ति योजना तथा महिला समेकित विकास योजनाओं को संचालित कर रही है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और समृद्धि प्राप्त हो सके।

- सरकार ने महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के बेहतर क्रियान्वयन, अनुरक्षण हेतु राज्य मिशन प्राधिकरण का गठन किया है।

(29) सरकार ने मद्य निषेद्य नीति को महत्व देते हुए राज्य के हित में उसके पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण द्वारा वैधानिक बिक्री द्वारा अधिकतम राजस्व उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।

(30) मेरी सरकार उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू-सैक) अपनी स्थापना से ही राज्य के विभिन्न रेखीय विभागों को अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी समर्थकृत साधनों-सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र एवं भूमण्डलीय स्थापन प्रणाली के उपयोग द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, आधारभूत विकास, जल संसाधन प्रबन्धन, बर्फ, हिमनद अनुश्रवण, जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण, कृषि बागवानी, औषधीय पादपों से

सम्बन्धित अध्ययनों एवं विकासात्मक संचार के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है।

- मेरी सरकार जैवप्रौद्योगिकी शिक्षा तथा अनुसंधान एवं विकास; मानव संसाधन विकास; आधुनिक जैवप्रौद्योगिकी का केन्द्र; (अ) सी0ई0एम0बी0 (ब) एम0डी0एल0 (मोलिक्युलर डाइग्नोस्टिक्स प्रयोगशाला); बायोटैक पार्क तथा; विज्ञान एवं समाज कार्यक्रमों पर विशेष बल दे रही है।
- सरकार जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आवश्यक विशेष तकनीकी के संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने हेतु दृढ़ संकल्पित है।
- सरकार जैव प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण तथा उसके प्रदर्शन से आय सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तथा रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने के कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ हो रहे पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।

सरकार आपदा राहत कोष, राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों का पुनरीक्षण करने, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र संचालित करने, आपदा सम्बन्धित सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु एस0एम0एस0 सेवा उपलब्ध कराने, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण व जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का संचालन, खोज एवं बचाव की उपलब्धता, कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा न्याय पंचायतों के अन्तर्गत खोज एवं बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कटिबद्ध है।

- सरकार भूकम्प सुरक्षित निर्माण हेतु राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण और संवेदनशील ग्रामों का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने के लिए कटिबद्ध है।
- राज्य में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन दल की बटालियन स्थापित करने हेतु जनपद उत्तरकाशी के स्थान सिरोड़ तथा जनपद अल्मोड़ा के स्थान सरियापानी में इसकी स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी गई है।

- सरकार नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन (एन.आई.डी.), अहमदाबाद के साथ प्रदेश के पारम्परिक शिल्पों पर आधारित सोविनियर विकास की परियोजना क्रियान्वित कर रही है। राज्य के परम्परागत शिल्पों पर आधारित सोविनियर विकास परियोजना के अन्तर्गत एन.आई.डी., अहमदाबाद द्वारा डिजाइन वर्कशाप के आयोजन जनपद उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा में किये जा रहे हैं।

- सरकार उत्तराखण्ड ऊन योजना, धागा कताई और वस्त्र बुनाई तथा प्याज उत्पादन योजना पर विशेष रूप से कार्य कर रही है। इसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

(31) सरकार ने राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन बनाने, सामान्य सेवा क्षेत्र स्थापित करने, राज्य डाटा सेन्टर की स्थापना करने, जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी स्थापित करने की दिशा में ठोस पहल करना आरम्भ किया है।

(32) उत्तराखण्ड राज्य एक सैन्य बाहुल्य राज्य है। वर्तमान में इनके परिवारों की संख्या लगभग एक लाख पचास हजार है। सरकार ने वीरता पदक विजेताओं को मिलने वाले लाभ तीस वर्ष के स्थान पर आजीवन अनुमन्य करा दिये हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्वयुद्ध पेंशन और आवासीय सहायता अनुदान को नियमित रूप से भुगतान करते हुए पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाऐं संचालित कर रही है।

- सरकार ने सशस्त्र सेवाओं में कार्यरत सैनिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु जनपद स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति का भी गठन किया है।

- सरकार विभिन्न खेलों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु कई लाभकारी योजनाएं संचालित कर रही है। विशेष प्रशिक्षण शिविर योजना के अन्तर्गत देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तथा पिथौरागढ़, देहरादून, कोटद्वार एवं हल्द्वानी में बालकों का आवासीय क्रीड़ा छात्रावास एवं अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग) में बालिका आवासीय क्रीड़ा छात्रावास संचालित कर रही है।

इन छात्रावासों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन, प्रशिक्षण, शिक्षण, किट एवं चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सरकार प्रदेशीय खेल संघों, क्लबों एवं अन्य खेल संघ से जुड़ी संस्थाओं को प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं खेल उपकरण के क्रय हेतु अनुदान दे रही है।

- एस.सी.एस.पी.एवं टी.एस.पी. योजना के अन्तर्गत बहुल्य क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन कर चुकी है।

**(33) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए दृढ़संकल्पित है।** इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए पर्यटन, दैवी आपदा, पशुपालन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन किया है।

**(34) देश की राजधानी नई दिल्ली से राज्य के विकास हेतु किए** जाने वाले कार्यों के सम्पादन में सुविधा की दृष्टि से चाणक्यपुरी स्थित उत्तराखण्ड निवास को परिवर्धित करने, आर्थिक राजधानी मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन का शीघ्र निर्माण करने तथा अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार आवास तैयार करने की कार्यवाही तत्परता से कर रही है।

पत्रकारों की सुविधा के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना, एवं मान्यता प्राप्त एवं श्रमजीवी पत्रकारों को पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता तथा राजकीय चिकित्सालयों में सरकारी कर्मचारियों की भाँति चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त पत्रकारों को राज्य सरकार की परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है तथा पत्रकार संगठनों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली गोष्ठियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है तथा प्रेस कल्बों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए भी धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

**(35) सरकार हिन्दी भाषा के सम्यक् विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, और** पुस्तक रचनाओं पर राज्य के विभिन्न मूर्धन्य व्यक्तियों के नाम पर पुरस्कार गठित करने की योजना पर भी विशेष कार्य कर रही है।

(36) सरकार सचिवालय के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे राज्य की जनता के नीति विषयक महत्वपूर्ण कार्यों का निस्तारण समयबद्ध रीति से सम्पादित हो सके।

(37) सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए सरकारी सेवा में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर चालीस वर्ष कर दिया है। इसके अतिरिक्त संविदा के अधीन आउटसोर्सिंग के भरे जाने वाले पदों पर भी आरक्षण दिए जाने का निर्णय सरकार द्वारा ले लिया गया है।

(38) सरकार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के बेहतर रख रखाव और जनता की सुविधा के लिए जहां उपनिबन्धक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करवा रही है, वहीं ई-स्टाम्पिंग प्रणाली लागू किये जाने की भी कार्यवाही प्रारम्भ की है। इसके अतिरिक्त विवाह पंजीकरण की कार्यवाही भी समयबद्ध रीति से सम्पादित कर रही है।

(39) सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु श्री के0आर0भाटी, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है, इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2005) के अधीन बनाये जाने वाले नियमों को सरल व उपयोगी बनाए जाने के अभिगत नए नियमों का गठन किया है।

मैनें अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखा है। मुझे आशा है कि आप सभी सदस्यगण लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करते हुए इस गरिमामयी सदन में राज्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने हेतु अपने बहुमूल्य विचार एवं सुझाव देंगे तथा आपसी सहयोग और सामंजस्य से राज्य की समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में सफल होंगे। मैं सम्मानित सदस्यगणों का आभार व्यक्त करते हुए वित्तीय और अन्य विधायी कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

जय हिन्द!